आईसीआईसीआई के निदेशक मंडल में बने रहेंगे लोक रंजन

नई दिल्ली 12 मई (ए)। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नौकरशाह लोक रंजन आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में बतौर स्वतंत्र निदेशक बने रहेंगे। मंत्रालय के

मुताबिक रंजन का तबादला कार्मिक मंत्रालय में हो गया है, लेकिन वे निदेशक मंडल में बने रहेंगे। सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव रंजन का तबादला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में कर दिया। इससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में बने नहीं रहेंगे। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा, ''लोक रंजन तबादले के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक होंगे।'' रंजन को पिछले महीने अप्रैल में आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान लिया जो वित्तीय सेवा विभाग में सयुक्त सचिव हैं। वह सोमवार और मंगलवार को आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में शरीक नहीं हुए। यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है कि जब बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी चंदा कोचर वीडियोकान को 3,250 करोड़ रुपए के कर्ज देने के मामले में हितों के टकराव का आरोप झेल रही है। सीबीआई ने वीडियोकान के संस्थापक वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सुब्रमणियम स्वामी ने आयकर समाप्त करने की वकालत की

हैदराबाद 12 मई (ए)। भाजपा सांसद सुब्रमणियम स्वामी ने मध्यम वर्ग से बोझ कम करने को आयकर समाप्त करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे देश में ऊंची आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि

अनिवार्य रूप से मध्यम वर्ग तथा स्टार्ट अप उद्यमियों की युवा पीढ़ी आयकर से सबसे अधिक प्रभावित होती है। यह एक तरह से उनका 'शोषण' है। स्वामी ने सवाल किया, ''भारत में आयकर कौन दे रहा है? बहुत छोटा वर्ग। ऐसे में इस छोटे वर्ग पर आप यह बोझ क्यों डाल रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि आयकर को समाप्त करने से लोगों की बचत बढ़ेगी और इससे निवेश में इजाफा होगा। संवाददाताओं से बातचीत में स्वामी ने कहा, ''ऐसे में इसे समाप्त करने से बचत की दर बढ़ेगी। बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा। इससे वृद्धि दर बढ़ेगी। ऐसे में आप आयकर से जो प्राप्त करते हैं उसे समाप्त करने के बाद अप्रत्यक्ष करों से अधिक हासिल करेंगे।'' स्वामी ने कहा कि आयकर समाप्त करने से राजस्व का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कोयला ब्लॉकों और स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से की जा सकती है। उन्होंने कहा, ''तभी मैं कह रहा हूं कि 2जी, 3जी, 4जी, 5जी की नीलामी करें। एक लंबी कतार है। आप कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर सकते हैं। सरकार को सभी प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी की जानी चाहिए। यह संसाधन जुटाने का तरीका है।''

जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम अप्रैल में 4.6% बढ़ा

मुंबई 12 मई (ए)। जीवन बीमा उद्योग ने नए वित्त वर्ष की अच्छी शुरूआत की और अप्रैल के दौरान नया प्रीमियम 4.6 प्रतिशत बढ़कर 7,280 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। परिषद ने आज कहा कि अप्रैल अंत तक नया व्यक्तिगत कारोबार

7.32 प्रतिशत बढ़कर 3,881.61 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि इसकी तुलना में नया सामूहिक कारोबार महज 1.60 प्रतिशत की दर से बढ़ा और 3,398.35 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान नए प्रीमियम में 27.74 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जीवन बीमा निगम शीर्ष पर बनी रही। एच.डी.एफ.सी. लाइफ ने 10.53 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंशियल को पछाड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

14,000 करोड़ के निर्यात रिफंड में तेजी लाई जाएगी: अधिकारी

नई दिल्ली 12 मई (ए)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत करीब 14,000 करोड़ रुपए का निर्यात रिफंड लंबित है। विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक एन के श्रीवास्तव ने आज कहा कि इस लंबित निर्यात रिफंड को तेजी से वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच इस बारे में बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां पीएचडी चैंबर आफ

कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीवास्तव ने हालांकि इसके लिए निर्यातक समुदाय पर ही दोष मढ़ते हुए कहा कि उनके द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ियां थीं। उन्होंने कहा, ''इसी वजह से निर्यात रिफंड में देरी हो रही है, लेकिन वाणिज्य और राजस्व विभाग के बीच इस बारे में बातचीत तेजी से जारी है। 14,000 करोड़ रुपए के लंबित रिफंड का वितरण जल्द कर दिया जाएगा।'' श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार देश के निर्यात को प्रोत्साहन के लिए इस समय क्षेत्र आधारित निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में वाणिज्य विभाग में एक समिति गठित की गई है जो विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात की क्षमताओं की समीक्षा करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हालत में सुधार नहीं

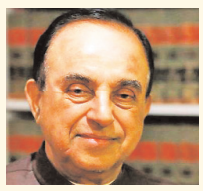

नई दिल्ली 12 मई (ए)। शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के नतीजे आए। इन बैंकों का घाटा पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का शुद्ध घाटा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में 4 गुना बढ़कर 2,134.36 करोड़ रुपए हो गया। वहीं केनरा बैंक के तिमाही नतीजे भी आ गए हैं। केनरा बैंक को चौथी तिमाही में 4,860 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक इलाहाबाद का हृक्क बढ़ जाने से 3,509.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन बैंकों के नुकसान से स्थिति स्पष्ट है कि हालत सुधरने की बजाय और तेजी से बिगड़ रही है। सिर्फ एनपीए ही नहीं बढ़ा है, बल्कि आय में भी गिरावट दर्ज की गई है।

इलाहाबाद बैंक को हुआ नुकसान: इलाहाबाद बैंक के एनपीए के प्रावधान में 3 गुना इजाफा करने से 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में एकल आधार पर 3,509.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वित्त वर्ष 2016-17 की समान तिमाही में उसे 111.16 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। इससे पहले दिसंबर तिमाही में भी बैंक को 1,263.79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आलोच्य तिमाही के दौरान बैंक की आय 5,105.07 करोड़ रुपए से कम होकर 4,259.88 करोड़ रुपए रह गई है। पूरे वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को 4,674.37 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि आय गिरकर 19,051.05 करोड़ रुपए पर आ गई है। इस दौरान

समग्र एनपीए 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 15.96 प्रतिशत पर पहुंच गया है। हालांकि शुद्ध एनपीए में कमी आई है और 8.92 प्रतिशत से कम होकर 8.04 प्रतिशत पर आ गया है।

केनरा बैंक को 4,859.77 करोड़ का नुकसान: केनरा बैंक के वित्तीय नतीजों को देखें तो पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2018) में बैंक के एनपीए के लिए प्रावधान की गई राशि में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते समीक्षाधीन तिमाही में केनरा बैंक को 4,859.77 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक तिमाही पहले (अक्तूबर-दिसंबर, 2017) बैंक ने 126 करोड़ रुपए, जबकि उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि यानी जनवरी-मार्च, 2017 में 214 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया था।

देना बैंक का शुद्ध घाटा: सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक की भी यही कहानी रही है। एनपीए में भारी बढ़ोतरी और इसके लिए प्रावधान की राशि बढ़ाने की वजह से बैंक को 1,225.42 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

आरबीआई जिम्मेदार: माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अन्य सरकारी व निजी बैंकों के आने वाले वित्तीय नतीजे भी कमोबेश ऐसे ही रहेंगे। दरअसल, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के नए निर्देशों को जिम्मेदार माना जा रहा है जिसने एनपीए निपटारे के आधा दर्जन पुराने नियमों को खत्म कर दिया है। नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं कि बैंक एनपीए की पहचान समय रहते कर सकें। इससे पहले बैंकों को यह सुविधा थी कि वे कर्जदारों को एनपीए चुकाने का एक और मौका देते थे। इससे उस राशि को एनपीए में दिखाने और उसके लिए अलग से राशि समायोजित करने की बाध्यता नहीं थी। नए नियमों के तहत बैंक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इससे न केवल एनपीए की राशि बढ़ी है, बल्कि उसके समायोजन के लिए भी बैंकों को ज्यादा रकम रखना पड़ रहा है।

नीरव मोदी स्टाइल में ओबीसी बैंक के साथ 155 करोड़ की धोखाधड़ी

नई दिल्ली 12 मई (ए)। हरियाणा की लकड़ी की एक कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के साथ 155 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर बैंक बुक में उल्लेख किए बिना फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनैशनल बैंकिंग मैसेज का इस्तेमाल करके सिंगापुर में अपनी सहायक कंपनी की स्वीकृत क्रेडिट सीमाओं में हेरफेर कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की।

बतां दें कि पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) के साथ धोखाधड़ी के लिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भी इसी तरह धोखाधड़ी की थी। अधिकारियों ने बताया कि एम.टी.पी.एल. ने आयातित

लकड़ी के व्यापार और आवरण में लगे हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक संघ से 242.09 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। बैंक को स्वीकृत नकद क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की गई। ओबीसी की शिकायत पर सीबीआई ने महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (एम.टी.पी.एल.) के निदेशकों अशोक मित्तल और निशा मित्तल, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौर करने वाली बात है कि रंगा को इस मामले मे बर्खास्त कर दिया गया है।

बैंकों को वित्त पोषण से पहले आभूषण क्षेत्र को समझना चाहिए: सुरेश प्रभु

नई दिल्ली 12 मई (ए)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रत्न और आभूषण उद्योग रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत है। इस वजह से इसके लिए ऐसी बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र को समझता हो और जो बगैर कोई जोखिम उठाए इस क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करे।

उन्होंने बैंकों से किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए उचित जोखिम बचाव तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। प्रभु ने रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, सोना, रत्न एवं आभूषण और हीरे का कारोबार भारत में बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। हम एक बैंकिंग प्रणाली चाहते हैं जो व्यापार को सही तरीके से समझती है। बैंकों को कोई भी बेमतलब का

जोखिम नहीं लेना चाहिए।'' रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च में पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के नीरव मोदी घोटाले के बाद व्यापार वित्तपोषण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले गारंटी पत्र (एलओयू) और आश्वासन पत्र (एलओसी) पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है जिसके बाद रत्न एवं आभूषण क्षेत्र वित्त पोषण की समस्या का सामना कर रहा है।

प्रभु ने कहा कि सरकार किसी भी ऐसी व्यावसायिक गतिविधि का समर्थन नहीं करेगी जो नैतिक न हो और बैंक के योग्य नहीं हो। पीएनबी धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हुए वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा कि बैंकों तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, बैंकिंग क्षेत्र को यह भी जानना चाहिए कि इस विफलता का कारण वास्तव में हमारी खुद की बैंकिंग प्रणाली की विफलता थीं। वाणिज्य सचिव ने बैंकों से लघु एवं मझोले उपक्रमों (एसएमई) क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। ये क्षेत्र वित्तपोषण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम एसएमई की उपेक्षा करते हैं तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को पीछे कर देंगे।

अप्रैल में जेएसडब्ल्यू स्टील का उत्पादन छह फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली 12 मई (ए)। घरेलू इस्पात कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील का कच्चे इस्पात का उत्पादन अप्रैल, 2018 में छह फीसदी बढ़कर 13.61 लाख टन पर पहुंच गया। सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली कंपनी का इस्पात उत्पादन अप्रैल, 2017 में 12.88 लाख टन रहा था। इस अवधि में कंपनी का फ्लैट रोल्ड उत्पादों यानी इस्पात की चादरों आदि का उत्पादन चार फीसदी बढ़कर 9.67 लाख टन रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 9.32 लाख टन था। इसी तरह कंपनी का लांग रोल्ड यानी सरिया,

एंगल आदि का उत्पादन नौ फीसदी बढ़कर 2.96 लाख टन से 3.24 लाख टन पर पहुंच गया। स्टील की चादरों एवं अन्य 'फ्लैट' उत्पादों का इस्तेमाल वाहन और टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्रों में होता है जबकि लंबे उत्पादों का इस्तेमाल मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में होता है।

वसीयत लिखने में गलतियां की तो बड़ी परेशानी

नई दिल्ली 12 मई (ए)। उम्र के एक पड़ाव पर आकर अक्सर लोग अपनी वसीयत बनवा ही लेते हैं। ऐसा कर वो अपनों को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। यानी उनके न रहने पर भी उनकी पत्नी और बच्चों को आर्थिक रुप से कमजोर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर लोग संपत्ति के वारिस का नाम कागजात में दर्ज करना भूल जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी वजह से कई अमीरों की मौत के बाद उनके कई वारिस सामने आ जाते हैं और फिर लंबा कानूनी विवाद चलता रहता है। आज जानिए वसीयत से जुड़ी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए।

वसीयत सही से तैयार नहीं करना: कई लोग वसीयत बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। आपको जरूरी निजी डिटेल्स जैसे नाम, पता, स्थान और तारीख के साथ-साथ लाभार्थी का पूरा नाम, संबंध और संपत्ति का सही-सही विवरण लिखना चाहिए।

विस्तार से दें पूरी जानकारी: अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी विस्तार से दें। इसके अलावा अन्य जानकारी जैसे अपने हर बैंक खाते, लॉकर नंबर्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स विस्तार में लिखें। इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा।

वसीयत को अपडेट करना ना भूलें: वसीयत बनाने के बाद अगर आपकी संपत्ति या वारिस की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो वसीयत को अपडेट करना ना भूलें। अगर किसी नाबालिग के नाम वसीयत तैयार करना चाहते हैं तो उसका गार्जियन भी जरूर नियुक्त करें। अगर गार्जियन नियुक्त रहता है तो वह नाबालिग के बालिग होने तक उसके केयरटेकर की भूमिका निभाता है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगेगी आग कर्नाटक चुनाव के बाद फिर बढ़ेंगे दाम

नई दिल्ली 12 मई (ए)। कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी को एक बार फिर से झटका दे सकती हैं। खबरों के मुताबिक तेल विपणन कंपनियां प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी करना चाहती हैं, लेकिन कंपनियों को डर है कि यदि अचानक पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ती है तो जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

24 अप्रैल से नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के रेट: तेल कंपनियों ने 24 अप्रैल से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है। माना जा रहा है कि तेल कंपनियों ने कर्नाटक चुनाव के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 24 अप्रैल से बदलाव नहीं करना इन्हें स्थिर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनावों के समय यह होना महज संयोग है।

कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर: दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतें पहले ही तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें अगले साल 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। वेनेजुएला और ईरान में सप्लाइ में कमी आने के चलते यह समस्या पैदा हो सकती है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तो 77 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर चल रहा है। बैंक का कहना है कि 2019 की दूसरी तिमाही तक यह आंकड़ा 90 डॉलर प्रति बैरल तक हो सकता है। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर उत्पादन में कमी की स्थिति है।

विदेशी मुद्रा भंडार में 1.43 अरब डॉलर की गिरावट

मुंबई 12 मई (ए)। देश का विदेशी मुद्रा भंडार चार मई को समाप्त सप्ताह में 1.426 अरब डॉलर घटकर 418.940 अरब डॉलर रह गया जिसका कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी आना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है। इसके अनुसार इससे पिछले सप्ताहांत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.216 अरब डॉलर घटकर 420.366 अरब डॉलर रह गया था। इससे पूर्व 13 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 426.028 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया था। आठ सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर को लांघने में कामयाब रहा थ्रा। लेकिन उसके बाद में इसमें उतार चढ़ाव रहा है। समीक्षाधीन सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.560 अरब डॉलर घटकर 393.716 अरब डॉलर रह गया। अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले एफसीए में मुद्रा भंडार में रखे गये यूरो, पौंड और जापानी येन जैसे गैर-अमेरिकी मुद्राओं की तेजी अथवा अवमूल्यन के प्रभावों को शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक ने बताया कि समीक्षाधीन सप्ताह में देश का स्वर्ण आरक्षित भंडार 15.07 करोड़ डॉलर बढ़कर 21.661 अरब डॉलर हो गया।

ट्रम्प के ईरान पर प्रतिबंध से भारत पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली 12 मई (ए)। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के फैसले का भारत पर व्यापक असर पड़ सकता है। अमरीका के एक वरिष्ठ राजनयिक का कहना है कि भारत को ईरान से तेल का आयात कम करने के लिए 6 महीने का समय मिलेगा। इन प्रतिबंधों के कारण भारत को अपने तेलशोधक संयंत्रों को वैकल्पिक कच्चे तेल के शोधन के लिए तैयार करना होगा। साथ ही भारत के रणनीतिक निवेशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिसे वह क्षेत्रीय हितों के लिए अहम मानता है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। यह भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को एक बार फिर उस क्षेत्र में अपने परमाणु जाल को फैलाने का मौका मिल सकता है। वॉशिंगटन में विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र और बैंकिंग, निर्यात तथा ऊर्जा के परिवहन से जुड़े प्रतिबंधों के मामले में 6 महीने की मोहलत दी गई है जबकि दूसरे प्रतिबंधों के

मामले में यह 90 दिन है।

भारत के कई अहम निवेश होंगे प्रभावित: अमरीकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में भारत के कई अहम निवेश प्रभावित होंगे। इनमें फारस की खाड़ी में फरजाद बी तेल क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. विदेश का निवेश शामिल है। इस पर भारत और ईरान ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए पिछले महीने सहमति जताई थी। नए समझौते के तहत इस तेल क्षेत्र से निकलने वाली गैस की खरीद और विपणन की जिम्मेदारी ईरान की होगी। जबकि भारतीय कम्पनी इसका विकास करेगी। इस पर 4 से 6 अरब डालर का निवेश होना अनुमानित है। प्रतिबंधों के कारण 50 करोड़ डालर से चाबहार बंदरगाह के विकास और इसे रेल मार्ग से अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोडने् की योजना भी प्रभावित हो सकती है।